

## न्यूनतम समर्थन मूल्य

### प्रलिस के लयः

MSP और इसकी गणना, खरीफ मौसम, रबी मौसम ।

### मेन्स के लयः

MSP और संबध मुद्दों का महत्त्व ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने **खरीफ वपिणन वर्ष** 2022-23 के लयि **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को मंजूरी दी है, जसिमें कहा गया है कदिरें उत्पादन की औसत लागत का कम-से-कम 1.5 गुना होंगी ।

- 14 खरीफ फसलों की दरों में 4% से 8% तक की बढ़ोतरी की गई है ।

## खरीफ सीज़नः

- इस सीज़न में फसलें जून से जुलाई माह तक बोई जाती हैं और कटाई सतिंबर-अक्टूबर माह के बीच की जाती है ।
- **फसलें**: इसके तहत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली और सोयाबीन आद शामिल हैं ।
- **राज्य**: असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमलिनाडु, केरल और महाराष्ट्र ।

## न्यूनतम समर्थन मूल्यः

- **परचियः**
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जसि पर सरकार कसिनों से फसल खरीदती है और यह कसिनों की उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना अधकि होती है ।
  - 'न्यूनतम समर्थन मूल्य'- कसिी भी फसल के लयि वह 'न्यूनतम मूल्य' है, जसि सरकार कसिनों के लयि लाभकारी मानती है और इसलयि इसके माध्यम से कसिनों का 'समर्थन' करती है ।
- **MSP के तहत फसलें**:
  - 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' द्वारा सरकार को 22 अधदिषिट फसलों (Mandated Crops) के लयि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लयि 'उचति और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सफिरशि की जाती है ।
    - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है ।
  - अधदिषिट फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणजियकि फसलें शामिल हैं ।
  - इसके अलावा लाही और नारयिल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) का नरिधारण क्रमशः सरसों और सूखे नारयिल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) के आधार पर कयिा जाता है ।
- **MSP की सफिरशि संबंधी कारकः**
  - कसिी भी फसल के लयि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफिरशि करते समय 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' द्वारा कृषि लागत समेत वभिनिन कारकों पर वचिर कयिा जाता है ।
  - यह फसल के लयि आपूर्ता एवं मांग की स्थति, बाज़ार मूल्य प्रवृत्तयिों (घरेलू व वैश्वकि), उपभोक्ताओं के नहितार्थ (मुद्रास्फीती), पर्यावरण (मटिटी तथा पानी के उपयोग) और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर भी वचिर करता है ।
- **तीन प्रकार की उत्पादन लागतः**
  - CACP द्वारा राज्य और अखलि भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लयि तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है ।
  - 'A2'

- इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, संचाई आदिपर किये गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
- 'A2+FL'
- इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिपति मूल्य शामिल किया जाता है।
- 'C2'
- यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्तियों के करिअ तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफाई करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - CACP द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतफल के लिये की जाती है।
  - जबकि 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बैचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।
- केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सफाई पर अंतिम निर्णय लेती है।
- **MSP की आवश्यकता:**
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कठिनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
  - वसुधैकरण (Demonetisation) और 'वस्तु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी, पंगु बना दिया है।
  - वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परिदृश्य विकट बना हुआ है।
  - डीज़ल, बजिली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया ही है।

## भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

- **सीमिता:** 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इन्होंने दोनों खाद्यान्नों का वितरण NFSA के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्त्वहीन ही है।
- **अप्रभावी रूप से लागू:** शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे हैं।
- **खरीद मूल्य के रूप में:** मौजूदा MSP व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य NFSA की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिससे इसका असतत्व न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय एक खरीद मूल्य के रूप में है।
- **गेहूँ और धान की प्रमुखता वाली कृषि:** चावल और गेहूँ के पक्ष में अधिक झुकी MSP प्रणाली इन फसलों के अति-उत्पादन की ओर ले जाती है तथा किसानों को अन्य फसलों एवं बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करती है, जबकि उनकी मांग अधिक है तथा वे किसानों की आय में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं।
- **मध्यस्थ-आश्रित व्यवस्था:** MSP-आधारित खरीद प्रणाली मध्यस्थों/बचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर निर्भर है, जिसे छोटे किसान अपनी पहुँच के लिये कठिन व जटिल पाते हैं।

## आगे की राह

- एक वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये आवश्यक है कि सरकार हमेशा तब हस्तक्षेप करे जब भी बाजार की कीमतें पूर्वनिर्धारित स्तर से नीचे गिरती हैं, मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन और अधिक आपूर्ति के मामले में अथवा जब अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कारणों के कारण मूल्य में गिरावट आती है।
- MSP को उन कई फसलों के लिये प्रोत्साहन मूल्य की तरह भी उपयोग किया जा सकता है जो पोषण सुरक्षा के लिये वांछनीय हैं (जैसे मोटे अनाज, दाल एवं खाद्य तेल) और जिनके लिये भारत आयात पर निर्भर है।
- अधिक पोषण गुणवत्ता वाले पशुपालन (मत्स्य पालन सहित) और फलों एवं सब्जियों में अधिक निवेश करना विकल्पपूर्ण होगा।
  - निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका नज्दी क्षेत्र को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर कुशल मूल्य शृंखला के निर्माण के लिये प्रोत्साहित करना है।
- सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन लाना चाहिये जहाँ कृषि मूल्य निर्धारण आंशिक रूप से राज्य-समर्थित हो और आंशिक रूप से बाजार-प्रेरित।
  - ऐसा करने का एक तरीका अंतर भुगतान योजना हो सकती है जैसा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'भावांतर भुगतान योजना' (BBY) के रूप में कार्यान्वयित की जा रही है।

## वर्ष के प्रश्न:

### प्रश्न: नमिनलखति कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद असीमिति है।
2. अनाज और दालों के मामले में MSP किसी भी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहाँ बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दोनों फसल मौसमों में 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है
- कुल खरीद मात्रा आमतौर पर उस विशेष वर्ष/मौसम के लिये वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिये। 25% की सीमा से अधिक खरीद के लिये कृषि विभाग (DAC) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- MSP को विभिन्न राज्यों द्वारा दिये गए MSP प्रस्तावों के औसत के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रस्ताव केंद्र की सिफारिश से अधिक हो सकते हैं। जबकि इनपुट लागत पर आधारित प्रस्ताव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, मूल्य असमानता से बचने के लिये MSP को तय किया जाता है। जब बाजार की कीमतें MSP से नीचे के स्तर तक गिर जाती हैं, तो सरकारी एजेंसियाँ किसानों की सुरक्षा के लिये उपज को खरीद लेती हैं। ऐसे में बाजार में कीमतें MSP से ऊपर जा सकती हैं। **अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प D सही है।**

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसि कृषिमें सार्वजनिक नविश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों की कृषि उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना
2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी का विकास
4. किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की छूट
6. सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: C

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस